



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 कार्तिक 1939 (श10)
(सं0 पटना 1040) पटना, बुधवार, 8 नवम्बर 2017

सं० 3ए-1-मुक०-26/2015-8703/वि०
वित्त विभाग

संकल्प

7 नवम्बर 2017

विषय:- वित्त विभागीय पत्रांक-177, दिनांक 07/01/2015 के द्वारा यक्ष्मा सहायक, स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत वेतनमान का वास्तविक लाभ दिए जाने के संबंध में।

1. स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत यक्ष्मा सहायकों द्वारा दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से वेतनमान रु० 4000-6000/- की स्वीकृति के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-21115/2013 तथा 21909/2013 दायर किया गया। उक्त दोनों रिट में संयुक्त रूप से माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक: 08.12.2014 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया-

"A direction is issued upon the respondent authorities, therefore, to provide the same pay scale and grade pay even now to the petitioners as that of BCG Technicians. The Court is not enthused to pass any order for granting any benefit of monetary kind or otherwise for the past by virtue of the order passed today but the benefit of parity with BCG Technicians will accrue from the date of this order and not create any other obligation or liability for the past upon the State."

उक्त न्यायादेश का अनुपालन वित्त विभागीय पत्रांक-177, दिनांक: 07/01/2015 द्वारा करते हुए दिनांक: 01/01/1996 से रु० 4000-6000 एवं 01/01/2006 से पीबी-1 ग्रेड पे 2400 की स्वीकृति दिनांक: 01/01/1996 से वैचारिक तथा 08/12/2014 से वास्तविक रूप से दी गई।

2. उक्त स्वीकृति से विक्षुब्ध होकर वादीगण द्वारा एल०पी०ए० सं०-334/2015 एवं 2033/2016 दायर किया गया। एल०पी०ए० सं०-2033/2016 में दिनांक:- 27/01/2017 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित है:-

"Thus, we find that when an employee is entitled to revision of pay in term of recommendation of the pay revision commission, such benefit can not be restricted only because of financial liability which will fall on the State, when the finding is of anomaly in fixation of pay scale.

Consequently, the LPA is allowed. The judgment of the learned single judge is modified by deleting the paragraph extracted above."

एल०पी० सं०-334/2015 में दिनांक: 08/02/2017 को पारित न्यायादेश निम्न प्रकार है:-

"The present Letters Patent Appeal is directed against an order passed on 8th of December, 2014 by learned single bench in CWJC No.-21909 of 2013.

Letters patent Appeal of 2016 (Nagendra Kr. Dikshit & Others vrs. The State of Bihar & Others) arising out of another analogous CWJC No.- 21115 of 2013 has been decided on 27 of January, 2017.

In view of the said fact, the present Letters Patent Appeal is disposed of in the same terms as in Narendra Kr. Dikshit Case (Supra)".

3. माननीय न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर एस०एल०पी० डायरी सं०-19567/2017 तथा 19563/2017, जो क्रमशः दिनांक- 04/09/2017 एवं 18/09/2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

4. उपर्युक्त बाध्यकारी स्थिति में यक्ष्मा सहायक, स्वास्थ्य विभाग के लिए दिनांक: 01/01/1996 के प्रभाव से 4000-6000/- का वेतनमान वैचारिक रूप से तथा 01/04/1997 से वास्तविक लाभ सहित एवं पीबी-1 ग्रेड-पे 2400/- का वेतनमान दिनांक 01/01/2006 से वैचारिक तथा 01/04/2007 से वास्तविक रूप से स्वीकृत करने का प्रश्न सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

5. अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि यक्ष्मा सहायक के लिए संकल्प सं०-660 दिनांक: 08.02.1999 के प्रावधानों के आलोक में दिनांक: 01/01/1996 से वैचारिक तथा 01/04/1997 से वास्तविक रूप से वेतनमान रु० 4000-6000/- एवं वित्त विभागीय संकल्प सं०-630 दिनांक:-21/01/2010 के प्रावधानों के आलोक में दिनांक 01/01/2006 से पीबी-1 ग्रेड-पे 2400/- वैचारिक तथा 01/04/2007 वास्तविक रूप से अनुमान्य होगा। पूर्व निर्गत वित्त विभागीय पत्रांक:-177, दिनांक 07/01/2015 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा तथा बकाया राशि का भुगतान किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1040-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>